



Daily करेंट अफेयर्स

➤ 04 OCTOBER 2025

NATIONAL AFFAIRS

1. सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय (MoMSME) ने वाराणसी, उत्तर प्रदेश में 'एमएसएमई सेवा पर्व-2025: विरासत से विकास' मनाया।



सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय (MoMSME) ने हाल ही में 28 से 30 सितंबर, 2025 तक रुद्राक्ष अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एवं सम्मेलन केंद्र, वाराणसी, उत्तर प्रदेश में 'MSME सेवा पर्व-2025: विरासत से विकास' का आयोजन किया। इस आयोजन का उद्देश्य प्रदर्शनियों, स्वच्छता अभियानों और महिला उद्यमियों के लिए समर्पित सत्रों के माध्यम से भारत की विरासत को बढ़ावा देना, कारीगरों का समर्थन करना और MSME क्षेत्र को मजबूत बनाना था।

- MSME सेवा पर्व-2025 का मुख्य उद्देश्य सांस्कृतिक गौरव को बढ़ावा देना, सामुदायिक सेवा को बढ़ावा देना और स्थानीय कारीगरों का समर्थन करना था। एक उल्लेखनीय पहल में एमएसएमई के लिए विपणन सहयोग बढ़ाने हेतु खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग (KVIC) और राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम (NSIC) के बीच एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर शामिल थे।

- इस कार्यक्रम का औपचारिक उद्घाटन केंद्रीय सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री जीतन राम मांझी और केंद्रीय सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम राज्य मंत्री सुश्री शोभा करंदलाजे ने किया। कार्यक्रम में वरिष्ठ

गणमान्य व्यक्तियों में केवीआईसी के अध्यक्ष मनोज कुमार, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास आयुक्त कार्यालय के अधिकारी और उत्तर प्रदेश सरकार के प्रतिनिधि शामिल थे।

- तीन दिवसीय प्रदर्शनी में स्थानीय कारीगरों और शिल्पकारों द्वारा बनाए गए उत्पादों को प्रदर्शित करने वाले 130 स्टॉल लगाए गए। इस कार्यक्रम में सामुदायिक सेवा और स्वच्छता जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए नमो घाट पर स्वच्छता कार्यक्रम नामक एक सफाई अभियान भी चलाया गया।

Key Points:-

(i) महिला उद्यमियों और स्वयं सहायता समूहों (SHGs) के लिए एक समर्पित सत्र, महिला परिचर्चा, आयोजित किया गया, जिससे उन्हें केंद्रीय मंत्री सुश्री शोभा करंदलाजे, MoMSME के साथ बातचीत करने और व्यापार समर्थन और विकास के अवसरों के बारे में जानकारी प्राप्त करने में मदद मिली।

(ii) कार्यक्रम के दौरान, विपणन सहयोग को बढ़ावा देने और MSME उत्पादों के लिए व्यापक बाजार पहुंच प्रदान करने, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के लिए समग्र पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने के लिए KVIC और NSIC के बीच एक औपचारिक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए।

(iii) MSME लाभार्थियों को प्रधानमंत्री विश्वकर्मा (PMV) लाभार्थियों को ऋण प्रमाण पत्र, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (PMEGP) लाभार्थियों को मार्जिन मनी सब्सिडी और ग्रामोदय विकास योजना (GVY) लाभार्थियों को टूलकिट के वितरण के माध्यम से लक्षित समर्थन प्राप्त हुआ, जिससे कारीगरों और उद्यमियों के लिए ठोस लाभ सुनिश्चित हुआ।

2. DEA : लघु बचत योजना (SSS) की ब्याज दरें वित्त वर्ष 26 की तीसरी तिमाही के लिए अपरिवर्तित रहेंगी।



आर्थिक कार्य विभाग
DEPARTMENT OF
ECONOMIC AFFAIRS

30 सितंबर, 2025 को, वित्त मंत्रालय (MoF) के अंतर्गत आर्थिक मामलों के विभाग (DEA) ने घोषणा की कि लघु बचत योजना (SSS) की ब्याज दरें वित्तीय वर्ष 2025-26 की तीसरी तिमाही (वित्त वर्ष 2026 की तीसरी तिमाही) के लिए, यानी 1 अक्टूबर, 2025 से 31 दिसंबर, 2025 तक, अपरिवर्तित रहेंगी और वित्त वर्ष 2026 की दूसरी तिमाही की दरें ही रहेंगी।

● यह लगातार सातवीं तिमाही है जिसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है, अंतिम संशोधन वित्त वर्ष 2024 की चौथी तिमाही में हुआ था।

Key Points:-

(i) लघु बचत योजनाएँ (SSS) भारत में सरकार समर्थित निवेश साधन हैं, जिन्हें देश भर में घरेलू बचत को बढ़ावा देते हुए सुरक्षित और निश्चित रिटर्न प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।

(ii) इन योजनाओं का प्रबंधन मुख्य रूप से आर्थिक मामलों के विभाग (DEA) द्वारा किया जाता है और इनका संचालन देश भर में नामित बैंकों और 1.5 लाख से अधिक डाकघरों के माध्यम से किया जाता है, जिससे व्यापक पहुँच सुनिश्चित होती है।

(iii) विभिन्न लघु बचत योजनाओं के अंतर्गत एकत्रित सभी जमाओं को राष्ट्रीय लघु बचत निधि (एनएसएसएफ) में जमा किया जाता है, जिसका उपयोग सरकार द्वारा विकास परियोजनाओं और अन्य वित्तीय आवश्यकताओं के वित्तपोषण के लिए

किया जाता है।

3. मध्य रेलवे सभी पाँच डिवीजनों में कवच लोको परीक्षण पूरा करने वाला पहला क्षेत्रीय रेलवे बन गया।



सितंबर 2025 में, मध्य रेलवे (CR) के महाप्रबंधक (GM) धर्मवीर मीणा ने हाल ही में मुंबई मंडल के पनवेल-रोहा खंड पर सोमटने, आष्टा और जीते स्टेशनों पर स्वदेशी रूप से विकसित स्वचालित ट्रेन सुरक्षा (ATP) प्रणाली, कवच के सफल लोको परीक्षणों का नेतृत्व किया। इसके साथ ही, मध्य रेलवे सभी पाँच मंडलों—मुंबई, भुसावल, नागपुर, पुणे और सोलापुर—में लोको परीक्षण पूरा करने वाला पहला क्षेत्रीय रेलवे बन गया, जिसने अपने 4,000 किलोमीटर लंबे रूट नेटवर्क में कवच के राष्ट्रव्यापी प्रक्षेपण को आगे बढ़ाया।

● स्वचालित ट्रेन सुरक्षा (ATP) प्रणाली कवच को आमने-सामने और पीछे से होने वाली दुर्घटनाओं सहित टकरावों को रोककर और सिग्नल पास्ड एट डेंजर (SPAD) घटनाओं को कम करके रेलवे सुरक्षा में सुधार करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जिससे यात्री और परिचालन सुरक्षा मजबूत होती है।

● कवच में उन्नत सुरक्षा कार्यक्षमताएं शामिल हैं जैसे सिग्नल छूट जाने पर स्वचालित ब्रेक लगाना, प्रतिबंधित क्षेत्रों में गति नियंत्रण, सिग्नल पहलुओं

और गति सीमाओं का ऑनबोर्ड प्रदर्शन, लेवल क्रॉसिंग पर स्वचालित सीटी बजाना और आपात स्थिति के लिए SOS संकट फ़ंक्शन।

● कार्यान्वयन में विस्तृत रेडियो और लिडार (लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग) सर्वेक्षणों को तेजी से पूरा करना, उसके बाद तकनीकी अनुमोदन, उपकरण आपूर्ति और प्रत्येक प्रभाग में पहचाने गए प्राथमिकता वाले स्टेशनों पर स्थापना शामिल थी।

Key Points:-

(i) इसके क्रियान्वयन हेतु, प्रत्येक मंडल में तीन स्टेशनों को कवच स्थापना हेतु प्राथमिकता केंद्रों के रूप में चुना गया है। महाराष्ट्र के भुसावल और कल्याण लोको शेड में ऑनबोर्ड फिटमेंट का कार्य चल रहा है, क्योंकि भारतीय रेलवे (IR) मध्य रेलवे के पहले कार्यान्वयन चरण में 730 इंजनों को सुसज्जित करने के लिए मिशन मोड में आगे बढ़ रहा है।

(ii) मध्य रेल ने अपने सभी मंडलों में नेटवर्क निगरानी, परीक्षण और प्रशिक्षण सुविधाएँ स्थापित की हैं। इसके अतिरिक्त, लगभग 3,000 अधिकारियों और कर्मचारियों को सुचारू तैनाती और एकीकरण सुनिश्चित करने के लिए कवच संचालन में प्रशिक्षित किया गया है।

(iii) 4-19 सितंबर, 2025 के बीच, मध्य रेलवे ने भुसावल में एकीकृत कवच नियंत्रण केंद्र का उद्घाटन किया, सोलापुर डिवीजन में प्रारंभिक लोको परीक्षण किए, कुरुदवाड़ी में एक सिमुलेशन लैब का शुभारंभ किया और भुसावल, पुणे और नागपुर डिवीजनों में स्टेशन-स्तरीय परीक्षण किए, जिससे उन्नत ट्रेन सुरक्षा प्रौद्योगिकी को अपनाने में इसका नेतृत्व मजबूत हुआ।

4. भारतीय नौसेना ने आत्मनिर्भर भारत के तहत उन्नत अंडरवाटर ड्रोन के लिए EyeROV के साथ 47 करोड़ रुपये का अनुबंध किया।



सितंबर 2025 में, भारतीय नौसेना (IN) ने भारत सरकार की "आत्मनिर्भर भारत" पहल का समर्थन करते हुए, उन्नत अंडरवाटर रिमोटली ऑपरेटेड व्हीकल्स (UWROVs) की आपूर्ति के लिए IROV टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड (EyeROV) के साथ 47 करोड़ रुपये के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए।

● इस समझौते में EyeROV ट्राउट की आपूर्ति शामिल है, जो एक सैन्य-ग्रेड UWROV है जिसे 300 मीटर तक के अंडरवाटर ऑपरेशन के लिए डिज़ाइन किया गया है और विशेष रूप से रक्षा और वाणिज्यिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।

● EyeROV ट्राउट 10x ऑप्टिकल ज़ूम के साथ 4K अल्ट्रा हाई डेफिनिशन प्राइमरी कैमरा, एक रोबोटिक आर्म और डॉपलर वेलोसिटी लॉग (DVL) और अल्ट्रा शॉर्ट बेसलाइन (USBL) ध्वनिक पोजिशनिंग जैसी उन्नत नेविगेशन प्रणालियों से लैस है।

● UWROVs आर्कटिक जल और ज्वालामुखीय क्षेत्रों जैसे चरम वातावरण में काम कर सकते हैं, और निगरानी, टोही, बुनियादी ढांचे के निरीक्षण और वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए उपयुक्त हैं, जो कई पेलोड विकल्पों के साथ लचीलापन प्रदान करते हैं।

BANKING & FINANCE

1. SEBI ने दावा न किए गए म्यूचुअल फंड निवेशों पर नज़र रखने और उन्हें पुनः प्राप्त करने के लिए MITRA प्लेटफॉर्म लॉन्च किया।



भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) ने सितंबर 2025 में म्यूचुअल फंड निवेश अनुरेखण और पुनर्प्राप्ति सहायक (MITRA) लॉन्च किया, जो निवेशकों को निष्क्रिय या दावा न किए गए म्यूचुअल फंड (MF) फोलियो का पता लगाने और उन्हें पुनः प्राप्त करने में मदद करने वाला एक नया डिजिटल प्लेटफॉर्म है।

- MITRA को दावा न किए गए या निष्क्रिय MF फोलियो की पहचान करने और उन्हें पुनः प्राप्त करने में निवेशकों की सहायता के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसका प्रबंधन दो योग्य रजिस्ट्रार और स्थानांतरण एजेंटों (QRTA), कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विसेज लिमिटेड (CAMS) और KFin टेक्नोलॉजीज लिमिटेड द्वारा संयुक्त रूप से किया जाएगा।

- लॉन्च के साथ ही, SEBI ने रिटेल एल्गोरिथम ट्रेडिंग नियमों के पूर्ण रोलआउट की समय-सीमा को 1 अप्रैल, 2026 तक बढ़ाने की घोषणा की। यह ढाँचा पहले 1 अगस्त, 2025 को लागू होना था, जिसे बाद में 1 अक्टूबर, 2025 तक के लिए टाल दिया गया।

Key Points:-

(i) SEBI ने रिटेल एल्गोरिथम फ्रेमवर्क के कार्यान्वयन के लिए तीन प्रमुख उपलब्धियाँ निर्धारित कीं: 31 अक्टूबर, 2025 तक कम से कम एक एल्गोरिथम रणनीति का पंजीकरण; 30 नवंबर, 2025 तक API-आधारित एल्गो का पूर्ण पंजीकरण; और 3 जनवरी, 2026 तक एक अनिवार्य मॉक ट्रेडिंग सत्र।

(ii) MITRA के लॉन्च और रिटेल एल्गोरिथम ट्रेडिंग में नियामक समायोजन के साथ, सेबी का लक्ष्य निवेशक सुरक्षा को बढ़ाना, दावा न किए गए धन तक पहुँच में सुधार करना और एल्गोरिथम-आधारित रिटेल भागीदारी के लिए एक संरचित ढाँचा सुनिश्चित करना है।

2. SIDBI ने MSME पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने के लिए 'उद्योग संघों का विकास (DIA)' योजना शुरू की।



सितंबर 2025 में, वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवा विभाग (DFS) के सचिव एम. नागराजू ने नई दिल्ली में आयोजित DIA पर राष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (SIDBI) की नई योजना 'उद्योग संघों का विकास (DIA)' का शुभारंभ किया। इस पहल का उद्देश्य एक स्थायी और नवोन्मेषी क्लस्टर विकास मॉडल के माध्यम से MSME की प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाना है।

- यह योजना पूरे भारत में लागत प्रभावी, नवीन और आत्मनिर्भर क्लस्टर विकास दृष्टिकोण को बढ़ावा देकर सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSMEs) को मजबूत करने के लिए तैयार की गई है।

- DIA MSMEs को बुनियादी ढांचे के निर्माण, कुशल जनशक्ति की उपलब्धता और विकास और प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ावा देने के लिए प्रारंभिक चरण की गतिविधियों के लिए समर्थन के लिए मांग-आधारित सहायता प्रदान करता है।

- सम्मेलन के दौरान DIA के साथ-साथ एक उद्योग पोर्टल भी लॉन्च किया गया। इस डिजिटल बिजनेस-टू-बिजनेस (B2B) प्लेटफॉर्म का उद्देश्य उद्योग संघों और उनके सदस्यों को सशक्त बनाना है।

Key Points:-

(i) यह पोर्टल अनुसंधान, नेटवर्किंग, सूचना साझा करने तथा उद्योग संघों और MSMEs के सामने आने वाली वित्तीय और तकनीकी चुनौतियों के समाधान के लिए एक केंद्र के रूप में काम करेगा।

(ii) DIA योजना और उद्योग पोर्टल का उद्देश्य MSME पारिस्थितिकी तंत्र को डिजिटल रूप से बदलना और मजबूत करना है, तथा इसे समावेशी आर्थिक विकास के प्रमुख चालक के रूप में स्थापित करना है।

3. RBI ने PSL मानदंडों का पालन न करने पर इंडियन ओवरसीज बैंक पर 31.8 लाख रुपये का जुर्माना लगाया।



सितंबर 2025 में, भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने इंडियन ओवरसीज बैंक (IOB) पर 'प्राथमिकता क्षेत्र ऋण (PSL) - लक्ष्य और वर्गीकरण' पर केंद्रीय बैंक के निर्देशों का पालन न करने पर 31.8 लाख रुपये का मौद्रिक जुर्माना लगाया।

Key Points:-

(i) यह जुर्माना बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46(4)(i) और 51(1) के साथ धारा 47ए(1)(सी) के तहत लगाया गया था, जो RBI को नियामक प्रावधानों का उल्लंघन करने वाले बैंकों के खिलाफ कार्रवाई करने का अधिकार देता है।

(ii) यह जुर्माना IOB के पर्यवेक्षी मूल्यांकन हेतु वैधानिक निरीक्षण (ISE 2024) के बाद लगाया गया है, जो RBI द्वारा 31 मार्च, 2024 तक की वित्तीय स्थिति के आधार पर किया गया था।

(iii) RBI के निरीक्षण से पता चला कि IOB ने 25,000 रुपये तक के कुछ प्राथमिकता क्षेत्र ऋण (PSL) ऋणों पर शुल्क लगाया था, जो निर्धारित PSL मानदंडों का उल्लंघन था।

4. RBI बैंक ने भारत भर में जीवन बीमा की पहुँच बढ़ाने के लिए LIC के साथ साझेदारी की।



30 सितंबर, 2025 को, आरबीएल बैंक लिमिटेड ने देश की सबसे बड़ी जीवन बीमा कंपनी, भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) के साथ एक रणनीतिक बैंकएश्योरेंस साझेदारी की घोषणा की। इस साझेदारी का उद्देश्य RBL बैंक के राष्ट्रव्यापी शाखा नेटवर्क और डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से LIC के जीवन बीमा उत्पादों की पूरी श्रृंखला उपलब्ध कराना है।

Key Points:-

- (i) यह गठबंधन पूरे भारत में RBL बैंक की भौतिक शाखाओं और डिजिटल चैनलों के माध्यम से ग्राहकों को LIC के उत्पादों तक आसान पहुँच प्रदान करके वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना और बीमा पहुँच का विस्तार करना चाहता है।
- (ii) इस साझेदारी के तहत, RBL बैंक LIC के जीवन बीमा उत्पादों की पूरी श्रृंखला वितरित करेगा, जिसमें टर्म इश्योरेंस प्लान, एंडोमेंट पॉलिसी, पेंशन स्कीम और यूनिट-लिंक्ड इश्योरेंस प्लान (ULIPs) शामिल हैं, जिससे ग्राहकों के लिए विविध कवरेज विकल्प सुनिश्चित होंगे।
- (iii) यह साझेदारी भारत के '2047 तक सभी के लिए बीमा' प्राप्त करने के लक्ष्य के अनुरूप है, जो एकीकृत वित्तीय नेटवर्क के माध्यम से शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में बीमा पहुँच को मजबूत करती है।

5. FatakPay की सहायक कंपनी 'फटकसेक्योर' को समग्र कॉर्पोरेट एजेंट लाइसेंस के लिए IRDAI की मंजूरी मिली।



सितंबर 2025 में, भारत के अग्रणी डिजिटल वित्तीय सेवा प्लेटफॉर्मों में से एक, फटकपे डिजिटल की सहायक कंपनी, फटकपे इश्योरेंस सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड (फटकसेक्योर) को भारतीय बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण (IRDAI) से समग्र कॉर्पोरेट एजेंट के रूप में कार्य करने की मंजूरी मिली।

Key Points:-

- (i) भारतीय बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण (IRDAI) ने फटकसेक्योर को यह समग्र कॉर्पोरेट एजेंट लाइसेंस प्रदान किया, जिससे वह औपचारिक रूप से बीमा क्षेत्र में अपने परिचालन का विस्तार कर सके और फटकपे के समग्र वित्तीय सेवा पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत कर सके।
- (ii) इस मंजूरी के साथ, फटकसेक्योर अब एक ही डिजिटल प्लेटफॉर्म के तहत विविध ग्राहक आवश्यकताओं को पूरा करते हुए, मोटर, स्वास्थ्य, दुर्घटना, जीवन, कॉर्पोरेट और उपभोज्य बीमा सहित बीमा उत्पादों की एक विस्तृत श्रृंखला वितरित कर सकता है।
- (iii) यह पहल मुख्य रूप से लाखों वंचित समुदायों, विशेष रूप से गिग श्रमिकों और ब्लू-कॉलर कर्मचारियों को बीमा पहुँच प्रदान करने पर केंद्रित है,

जिससे पूरे भारत में समावेशी वित्तीय सुरक्षा और कवरेज को बढ़ावा मिलता है।

6. अमेज़न पे ने भारत में डिजिटल लेनदेन को सरल बनाने के लिए 'पेमेंट्स का ए टू जेड' UPI प्लेटफॉर्म लॉन्च किया।



सितंबर 2025 में, अमेज़न पे ने निर्बाध डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा देने और भारत सरकार की कैशलेस अर्थव्यवस्था की पहल का समर्थन करने के लिए "पेमेंट्स का ए टू जेड" नाम से अपना नया यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस (UPI) प्लेटफॉर्म लॉन्च किया। यह नया फीचर आसान पहुंच और उपयोग के लिए कई भुगतान विकल्पों को एक ही प्लेटफॉर्म पर एकीकृत करता है।

- अमेज़न पे द्वारा हाल ही में लॉन्च किया गया UPI अपडेट UPI, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, अमेज़न पे बैलेंस और अमेज़न पे लेटर को एक एकीकृत भुगतान प्रणाली में जोड़ता है, जिससे अधिक सुविधाजनक और कनेक्टेड डिजिटल लेनदेन अनुभव सुनिश्चित होता है।

- यह एक डैशबोर्ड के माध्यम से एकीकृत भुगतान विकल्प प्रदान करता है, जिससे उपयोगकर्ता अपने सभी सहेजे गए भुगतान मोडों तक एक ही स्थान पर पहुंच सकते हैं, जिससे लेनदेन दक्षता और सुविधा बढ़ जाती है।

- यह प्लेटफॉर्म उपयोगकर्ताओं को एक ही इंटरफेस के तहत ऑटो-पे, बिल रिमाइंडर, सदस्यता और रिफंड ट्रैकिंग का प्रबंधन करने की अनुमति देकर व्यापक बिल प्रबंधन प्रदान करता है, जिससे वित्तीय संगठन सरल हो जाता है।

Key Points:-

(i) वैयक्तिकृत पुरस्कारों के माध्यम से, उपयोगकर्ता रुपये मूल्य में अनुकूलित कैशबैक ऑफ़र और छूट देख सकते हैं। यह स्मार्ट भुगतान सुझाव भी प्रदान करता है, जिससे उपयोगकर्ताओं को सबसे लाभदायक भुगतान विकल्प चुनने में मदद मिलती है।

(ii) अमेज़न पे ने वॉलेट UPI सुविधा शुरू की, जिससे ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों उपयोग के लिए एक-क्लिक भुगतान संभव हो गया, यहां तक कि कमजोर नेटवर्क कनेक्टिविटी वाले क्षेत्रों में भी, जिससे सभी क्षेत्रों में डिजिटल पहुंच का विस्तार हुआ।

(iii) इस सेवा का लाभ Amazon.in ऐप (नीचे नेविगेशन बार पर वॉलेट आइकन) और एंड्रॉइड डिवाइस पर Amazon Pay शॉर्टकट के ज़रिए उठाया जा सकता है। ब्रांड ने "पेमेंट्स का A से Z" नामक एक नया प्रचार अभियान भी शुरू किया है, जिसमें बॉलीवुड अभिनेता आयुष्मान खुराना भी शामिल हैं।

MOUs and Agreement

1. जल शक्ति मंत्रालय ने भावनगर, गुजरात में 'समुद्र से समृद्धि' कार्यक्रम में 66,000 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य के 27 समझौता ज्ञापनों का आदान-प्रदान किया।



सितंबर 2025 में, पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय (MoPSW) ने भावनगर, गुजरात में आयोजित "समुद्र से समृद्धि - भारत के समुद्री क्षेत्र में परिवर्तन" कार्यक्रम के दौरान 66,000 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य के 27 समझौता ज्ञापनों (MoU) के आदान-प्रदान की घोषणा की। इन समझौता ज्ञापनों में सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के हितधारक, राज्य सरकारें और अंतर्राष्ट्रीय साझेदार शामिल थे, जो समुद्री बुनियादी ढाँचे और रणनीतिक साझेदारियों को बढ़ाने के भारत के प्रयासों को रेखांकित करते हैं।

- हस्ताक्षर समारोह में केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल (MoPSW), डॉ. मनसुख मंडाविया (श्रम और रोजगार मंत्रालय और युवा मामले और खेल मंत्रालय), और केंद्रीय राज्य मंत्री (MoS) शांतनु ठाकुर (MoPSW) ने भाग लिया, जिन्होंने इस आयोजन के राष्ट्रीय महत्व पर प्रकाश डाला।

- गुजरात मैरीटाइम बोर्ड (GMB) ने राज्य स्तरीय समुद्री परिचालन को मजबूत करने के लिए एक्ट इंफ्रा पोर्ट्स लिमिटेड, मोडेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, चौगुले एंड कंपनी और स्वान डिफेंस एंड हैवी इंडस्ट्रीज लिमिटेड (स्वान डिफेंस) जैसे निजी भागीदारों के साथ 13,600 करोड़ रुपये से अधिक के कई समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए।

Key Points:-

(i) इस कार्यक्रम में महत्वपूर्ण समुद्री परियोजनाओं

का उद्घाटन किया गया, जिसमें गुजरात के छारा बंदरगाह पर एचपीएलएनजी (हजीरा पोर्ट लिक्विफाइड नेचुरल गैस) रीगैसिफिकेशन टर्मिनल और प्रमुख नवीकरणीय ऊर्जा (RE) पहल शामिल हैं, जो समुद्री बुनियादी ढाँचे के आधुनिकीकरण पर सरकार के फोकस को प्रदर्शित करता है।

(ii) पारादीप बंदरगाह प्राधिकरण, विशाखापत्तनम बंदरगाह प्राधिकरण, सागरमाला वित्त निगम लिमिटेड और ओडिशा सरकार द्वारा ओडिशा में 21,500 करोड़ रुपये के निवेश से एक नया बंदरगाह स्थापित करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए, जिसका उद्देश्य क्षेत्रीय व्यापार और संपर्क को बढ़ावा देना है।

(iii) प्रकाशस्तंभ महानिदेशालय ने समुद्री विरासत पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए गुजरात के लोथल में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर (NMHC) में 77 मीटर की ऊंचाई के साथ 266 करोड़ रुपये मूल्य के विश्व के सबसे ऊंचे प्रकाशस्तंभ संग्रहालयों के निर्माण के लिए भारतीय बंदरगाह रेल एवं सड़क मार्ग निगम के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।

APPOINTMENTS & RESIGNATIONS

1. लेफ्टिनेंट जनरल वीरेंद्र वत्स ने NCC के 35वें महानिदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया।



1 अक्टूबर, 2025 को लेफ्टिनेंट जनरल वीरेंद्र वत्स ने राष्ट्रीय कैडेट कोर (एनसीसी) के 35वें महानिदेशक (डीजी) के रूप में पदभार ग्रहण किया। वह लेफ्टिनेंट जनरल गुरबीरपाल सिंह का स्थान लेंगे, जो 30 सितंबर, 2025 को सेवानिवृत्त हुए थे। उनके नेतृत्व में, दुनिया का सबसे बड़ा वर्दीधारी युवा संगठन, एनसीसी, 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों (यूटी) में अपने कैडेटों की संख्या 20 लाख तक बढ़ाने के लिए तैयार है।

● लेफ्टिनेंट जनरल वीरेंद्र वत्स ने एनसीसी के 35वें महानिदेशक का पदभार संभाला, उन्होंने लेफ्टिनेंट जनरल गुरबीरपाल सिंह से पदभार ग्रहण किया, जिससे संगठन में एक महत्वपूर्ण नेतृत्व परिवर्तन हुआ।

● उनके कार्यकाल के दौरान, एनसीसी की योजना कैडेट संख्या को 20 लाख तक बढ़ाने की है, जो सभी 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों को कवर करेगी, जिससे देश भर में युवा जुड़ाव और नेतृत्व विकास को बढ़ावा मिलेगा।

● लेफ्टिनेंट जनरल वीरेंद्र वत्स 17 दिसंबर, 1988 को 19 कुमाऊं रेजिमेंट में भारतीय सेना में शामिल हुए और अपने साथ दशकों का सैन्य अनुभव लेकर आए।

Key Points:-

(i) लेफ्टिनेंट जनरल वीरेंद्र वत्स को अरुणाचल प्रदेश (AR), कश्मीर में तैनाती और सेना मुख्यालय में सेवा के साथ उग्रवाद-रोधी और आतंकवाद-रोधी अभियानों का व्यापक अनुभव है।

(ii) लेफ्टिनेंट जनरल वत्स ने कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में संयुक्त राष्ट्र (UN) मिशन के तहत एक इन्फैंट्री ब्रिगेड की कमान संभाली, जिससे उनके अंतर्राष्ट्रीय परिचालन नेतृत्व का प्रदर्शन हुआ।

(iii) NCC के महानिदेशक बनने से पहले, उन्होंने डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज, वेलिंगटन (न्यूजीलैंड)

के कमांडेंट के रूप में कार्य किया, तथा प्रशिक्षण और विकास भूमिकाओं में अपने पूर्व नेतृत्व का प्रदर्शन किया।

AWARDS

1. मुकेश अंबानी ने एम3एम हुरुन इंडिया रिच लिस्ट 2025 के 14वें संस्करण में शीर्ष स्थान हासिल किया।



सितंबर 2025 में, M3M इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने हुरुन रिसर्च इंस्टीट्यूट के साथ मिलकर M3M हुरुन इंडिया रिच लिस्ट का 14वां संस्करण जारी किया। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (RIL) के अध्यक्ष मुकेश अंबानी 9.55 लाख करोड़ रुपये की कुल संपत्ति के साथ भारत के सबसे अमीर व्यक्ति के रूप में शीर्ष स्थान पर पहुँच गए, और गौतम अडानी और उनके परिवार को पीछे छोड़ दिया, जो दूसरे स्थान पर खिसक गए। पहली बार, रोशनी नादर और उनका परिवार शीर्ष 3 में शामिल होकर भारत की सबसे अमीर महिला बन गईं।

● इस साल की सूची में 1,687 ऐसे व्यक्ति शामिल हैं जिनकी कुल संपत्ति 1,000 करोड़ रुपये या उससे ज्यादा है, जो 2024 की तुलना में 148 और पिछले पाँच सालों की तुलना में 859 की वृद्धि दर्शाता है। भारत में अब 358 अरबपति हैं, जो 13 साल पहले इस सूची के पहली बार प्रकाशित होने की तुलना में छह गुना ज्यादा है।

● मुकेश अंबानी 9.55 लाख करोड़ रुपये के साथ शीर्ष पर हैं, गौतम अडानी और परिवार 8.15 लाख करोड़ रुपये के साथ दूसरे स्थान पर हैं, और रोशनी नादर और परिवार 2.84 लाख करोड़ रुपये के साथ तीसरे स्थान पर हैं, जो भारत की सबसे अमीर महिला हैं।

● सूची में शामिल सभी व्यक्तियों की संयुक्त संपत्ति 167 लाख करोड़ रुपये है, जो 5% वार्षिक वृद्धि को दर्शाती है, जो भारत के सकल घरेलू उत्पाद (GDP) के लगभग 50% के बराबर है।

Key Points:-

(i) मुंबई (महाराष्ट्र) 451 अरबपतियों के साथ शीर्ष अरबपति केंद्र बना हुआ है, इसके बाद नई दिल्ली (दिल्ली) 223 अरबपतियों के साथ और बेंगलुरु (कर्नाटक) 116 अरबपतियों के साथ दूसरे स्थान पर है।

(ii) फार्मास्यूटिकल्स क्षेत्र का दबदबा कायम है, जिसमें 137 व्यक्ति सूची में हैं, इसके बाद औद्योगिक उत्पाद (132) और रसायन एवं पेट्रोकेमिकल्स (125) क्षेत्र हैं।

(iii) AI स्टार्टअप पर्लेक्सिटी के संस्थापक अरविंद श्रीनिवास (31 वर्ष) 21,900 करोड़ रुपये की संपत्ति के साथ भारत के सबसे युवा अरबपति बनकर उभरे। अरिस्टा नेटवर्क्स की सीईओ जयश्री उल्लाल 50,170 करोड़ रुपये की संपत्ति के साथ पेशेवर प्रबंधकों में शीर्ष पर हैं। महिलाओं में, 26 डॉलर अरबपतियों सहित 101 महिलाओं को शामिल किया गया, जिनमें प्रिस्टिन केयर की सह-संस्थापक डॉ. गरिमा साहनी (39 वर्ष) सबसे कम उम्र की स्व-निर्मित महिला उद्यमी बनीं।

IMPORTANT DAYS

1. संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस (IDOP) 2025-1 अक्टूबर को मनाया गया।



UNITED NATIONS
INTERNATIONAL DAY
OF OLDER PERSONS
(IDOP) 2025

OBSERVED ON

1ST OCTOBER

संयुक्त राष्ट्र (UN) वृद्धजनों के सम्मान और उनके अधिकारों, कल्याण और समाज में उनके योगदान के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रतिवर्ष 1 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस (IDOP) मनाता है। यह दिवस वृद्धजनों के लिए समावेशी नीतियों और सामाजिक समर्थन की आवश्यकता पर प्रकाश डालता है।

● IDOP 2025 का विषय है "स्थानीय और वैश्विक कार्यवाही को आगे बढ़ाने वाले वृद्ध व्यक्ति: हमारी आकांक्षाएं, हमारा कल्याण और हमारे अधिकार", जिसका उद्देश्य वृद्ध व्यक्तियों को उनके अधिकारों की रक्षा करते हुए स्थानीय और वैश्विक विकास में सक्रिय रूप से योगदान करने के लिए सशक्त बनाना है।

● IDOP का पालन 1982 में वृद्धावस्था पर आयोजित विश्व सभा से शुरू हुआ, जिसने वृद्धावस्था पर वियना अंतर्राष्ट्रीय कार्य योजना को अपनाया था।

● संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) ने 14 दिसंबर 1990 को संकल्प A/RES/45/106 के माध्यम से 1 अक्टूबर को आधिकारिक तौर पर IDOP के रूप में नामित किया।

Key Points:-

(i) IDOP पहली बार 1 अक्टूबर 1991 को विश्व स्तर पर मनाया गया था, जो वृद्ध व्यक्तियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय मान्यता की शुरुआत और दुनिया भर में

उनकी गरिमा, कल्याण और अधिकारों को बढ़ावा देने का प्रतीक था।

(ii) भारत में, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय (MoSJE) के तहत सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग (DoSJE) ने 1 अक्टूबर को डॉ. अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय केंद्र, नई दिल्ली में "सम्मान के साथ वृद्धावस्था" विषय के तहत आईडीओपी 2025 मनाया, जिसमें बुजुर्ग आबादी को समर्थन देने के लिए पहल पर प्रकाश डाला गया।

OBITUARY

1. वयोवृद्ध गांधीवादी और स्वतंत्रता सेनानी डॉ. जी.जी. पारिख का 101 वर्ष की आयु में निधन हो गया।



भारत के गांधीवादी समाजवादी आंदोलन के एक दिग्गज और प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी डॉ. गुणवंतराय गणपतलाल (जी.जी.) पारिख का 2 अक्टूबर, 2025 को 101 वर्ष की आयु में निधन हो गया। गांधी जयंती के दिन उनका निधन - जिस दिन वे अत्यंत श्रद्धा रखते थे - भारत की स्वतंत्रता के बाद की सामाजिक सक्रियता के एक युग के अंत का प्रतीक है।

• डॉ. पारिख ने 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया और बाद में आपातकाल के दौरान जेल भी गए। उन्होंने कांग्रेस पार्टी की समाजवादी शाखा की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका

निभाई और जीवन भर लोकतांत्रिक समाजवाद के एक समर्पित समर्थक रहे।

Key Points:-

(i) 1958 में, डॉ. पारिख ने महाराष्ट्र के पनवेल में यूसुफ मेहरअली केंद्र की स्थापना की। यह संस्थान ग्रामीण विकास, आत्मनिर्भरता, खादी और हाशिए पर पड़े समुदायों के सशक्तिकरण को बढ़ावा देने का केंद्र बन गया।

(ii) अहिंसा और आत्मनिर्भरता के सिद्धांतों पर चलते हुए, डॉ. पारिख ने खादी पहनी, डॉक्टर बनकर जीविकोपार्जन किया और खुद को जमीनी स्तर के सामाजिक कार्यों के लिए समर्पित कर दिया। गांधीवादी आदर्शों के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता के कारण उन्हें प्यार से "समाजवादियों का संत" कहा जाता था।

(iii) अपनी दिवंगत पत्नी मंगलाबेन पारिख के साथ किए गए संकल्प का पालन करते हुए, डॉ. पारिख ने अपना शरीर मुंबई के सर जे.जे. अस्पताल को दान कर दिया। निस्वार्थ सेवा का यह कार्य समाज की भलाई और चिकित्सा शिक्षा के उत्थान के लिए उनके आजीवन समर्पण को दर्शाता है।

Static GK

Ministry of Ports, Shipping and Waterways (MoPSW)	केंद्रीय मंत्री: सर्बानंद सोनोवाल	मुख्यालय: नई दिल्ली
Uttar Pradesh(UP)	मुख्यमंत्री (CM) : योगी आदित्यनाथ	राज्यपाल : आनंदीबेन पटेल
Ministry of Finance (MoF)	केंद्रीय मंत्री: निर्मला सीतारमण	मुख्यालय: नई दिल्ली
SEBI	अध्यक्ष: तुहिन कांता पांडे	मुख्यालय: मुंबई
SIDBI	मुख्यालय: लखनऊ, उत्तर प्रदेश	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक: मनोज मित्तल
RBI	राज्यपाल: संजय मल्होत्रा	मुख्यालय: मुंबई
IRDAI	अध्यक्ष: अजय सेठ	मुख्यालय: हैदराबाद
Hurun Report Inc. (Hurun Report)	मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) : रूपोर्ट हूगेवेर्फ़	मुख्यालय: लंदन, यूनाइटेड किंगडम (UK)